

## नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व भूमंडलीकरण

### सारांश

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वस्तुतः एक समता मूलक न्याय व सहभागी प्रकृति की वैश्विक अर्थव्यवस्था है। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को केवल किसी नए अर्थतंत्र अथवा नए आर्थिक आयामों की स्थापना के रूप में नहीं समझा जाना चाहिये। वरन यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे परिवर्तन का पर्याय है जिसमें विकासशील राष्ट्र अपनी स्वतंत्र पहचान, राजनीतिक अस्तित्व एवं निर्णायक सदस्य के रूप में उभर सकें। वस्तुतः विश्व स्तर पर विकसित राष्ट्रों की राजनीति ने ही समस्त विकासशील राष्ट्रों के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित किया है जिसे ये विकासशील राष्ट्र प्रभाव मुक्त करना चाहते हैं। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना अथवा आर्थिक आयामों के अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पक्षों जैसे नवीन अर्थव्यवस्था की मांग, यूरोप का एकीकरण, अमेरिकी हस्तक्षेप नीति तथा अधिनायक पूर्ण रवैया, अन्य विकसित राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि का अमेरिका को मुंह बंद समर्थन, अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद, सीटीबीटी आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करना आवश्यक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समग्ररूप में देखने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिलक्षित होने वाली एक ऐसी व्यवस्था जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति व विकास दोनों ही का मिश्रित परिणाम है तथा जिसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, का नवीनतम स्वरूप है।



### सुलोचना

शोध छात्रा,

(टी. आर. एफ.)

राजनीति विज्ञान विभाग,

राजकीय डूंगर महाविद्यालय,

बीकानेर

**मुख्य शब्द :** नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, खुली विश्व व्यवस्था, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा स्फीति, औद्योगिकीकरण, मानव विकास सूचकांक, तृतीय विश्व, संरक्षणवाद, भूमंडलीकरण, मुक्त व्यापार, नव उपनिवेशवाद, राष्ट्रीय सम्प्रभुता।

### प्रस्तावना

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ वस्तुतः एक ऐसी खुली विश्व व्यवस्था से है जो "वसुधैव कुटुम्बकम्" व "जियो और जीने दो" के सिद्धान्त पर आधारित हो, जहां बड़े-छोटे का भेद न हो, जहां समतामूलक, न्यायमूलक व सहभागी प्रवृत्ति विद्यमान हो, जहां दुनिया के समस्त राष्ट्रों की समुचित स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करते हुये समग्र विकास हेतु वैश्विक परिवेश उपलब्ध हो। इसी भावना के तहत 2 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र के छोटे अधिवेशन में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया।<sup>1</sup> इस प्रस्ताव के तहत विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं के पुनर्गठन पर सहमति बनी ताकि विश्व आर्थिक असमानता को कम किया जा सके।

विकासशील राष्ट्रों के मन में यह तथ्य सदैव विद्यमान रहता है कि उनका विकास विकसित राष्ट्रों की इच्छानुरूप न होकर स्वतंत्र होना चाहिए। विकसित राष्ट्र उन्हें केवल कच्चे माल उत्पादक उपनिवेश के रूप में न मानकार उनके स्वतंत्र विकास को प्रोत्साहित करें, ताकि विकासशील राष्ट्रों की सम्प्रभुता, विकास की उपलब्धियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान तथा अपनी नई अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सकें। यही संकल्पना नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जन्मदात्री है। इसलिए नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा से यही अभिप्राय रखा गया है कि विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्र जो आर्थिक स्वावलंबन के लिए दृढ़ संकल्प हैं, साम्राज्यवाद से मुक्त होकर अपना विकास करें तथा इस अर्थव्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य व्यापार व्यवस्था में अपेक्षित सुधार को समाहित करना भी रखा गया है। विकसित राष्ट्रों ने भूमंडलीकरण की बात प्रारंभ अवश्य की है परंतु उनका उद्देश्य भूमंडलीकरण के द्वारा साम्राज्यवाद का विस्तार भी है। उनका

ध्येय विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक आत्मनिर्भरता न होकर वरन् अपने लिए बाजारोन्मुख क्षेत्र के विस्तार के रूप में ही रहा है, जबकि विकासशील राष्ट्रों ने भूमंडलीकरण की धारणा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप में लिया। वे समस्त विश्व को आर्थिक क्रिया का क्षेत्र मानते हैं जिसमें मुक्त व्यापार, स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाएं एवं स्वैच्छिक विकास का अस्तित्व संभव है।

#### साहित्यावलोकन

एम. पी. राव. द्वारा सम्पादित, "द न्यू इन्टरनेशनल इकोनोमिक आर्डर" (2004) में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिचय, विकास, अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास व उपलब्धियों पर व्याख्या की गई है जो प्रस्तुत शोध के लिए उपयोगी है।

गिलपिन-गिलपिन की पुस्तक, 'ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनोमी: अण्डरस्टेन्डिंग द इन्टरनेशनल इकोनोमिक आर्डर (2011) (अमेजन डॉट कॉम) नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विस्तारित अध्ययन के कारण शोध में उपयोगी रहेगी। इसमें नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इतिहास व राजनीतिक प्रयासों पर चर्चा की गई है।

रेफेल व विलियम आर थॉम्पसन की पुस्तक "नॉर्थ एण्ड साउथ इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनोमी" (2008) में उत्तर-दक्षिण संवाद पर चर्चा की गई है। विकसित व विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व अर्थव्यवस्था में भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। यह इस शोध में उपयोगी रहेगी।

नियोल गेस्टन व अहमद एस खालिद द्वारा सम्पादित "ग्लोबलाइजेशन एण्ड इकोनोमिक इन्टिग्रेसन: विनर्स एण्ड लूजर्स इन द एशिया-पेसिफिक" (2010), में भूमंडलीकरण पर की गई व्याख्या प्रस्तुत शोध के लिये महत्वपूर्ण है।

सिंह हरवीर की पुस्तक 'दक्षेस संघ' लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (प्रकाशन बी एस शर्मा एण्ड ब्रदर्स (आगरा) संस्करण 2003 पृष्ठ 342) में लेखक ने राजनीतिक सामरिक एवं आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु क्षेत्रीय सहयोग की महत्ता पर बल दिया है।

महला अशोक के शोध कार्य "नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था" विकासशील देशों का दृष्टिकोण (सन् 1990 से 2000 तक), 2003 में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किये गये प्रयास व विकासशील देशों के योगदान का मूल्यांकन किया गया है। साथ ही भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिचय, इतिहास व अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के सन्दर्भ में यह अध्ययन उपयोगी रहेगा।

#### अध्ययन के उद्देश्य

1. भूमंडलीकरण की संकल्पना का ठहराव एवं संभावित दशा क्या होगी इसके लिए भूमंडलीकरण, इसके प्रभावों एवं आने वाले समय में इसके समालोचनात्मक स्वरूप को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन।
2. राजनीतिक मतभेदों के उपरान्त भी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर विभिन्न देशों की पारस्परिक सहयोगात्मक भावना ने आर्थिक पक्ष की वैश्विक

उपादेयता को सिद्ध किया है। यह पक्ष (आर्थिक) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक सहयोग द्वारा संबंधों को बनाए रखने की महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः इसका अध्ययन करना अहम उद्देश्य है।

3. आज सम्पूर्ण विश्व का श्रेणी विभाजन विकसित, विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्रों में हो गया है। यह विभाजन सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है तथा विकसित राष्ट्रों द्वारा शेष दो वर्गों को भयभीत कर रखा है। अतः विकासशील राष्ट्रों को जो अपने आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठा चुके हैं, की समस्याओं, संभावनाओं एवं पारस्परिक सहयोग के अलावा अपनाई विधियों का अध्ययन आवश्यक है।
4. नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन करना भी अध्येयता का उद्देश्य है।

#### परिकल्पना

परिकल्पना के रूप में निम्न अनुत्तरित प्रश्नों का निर्धारण किया गया है—

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता एवं राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही यह महसूस किया जा रहा था कि विकास के इन दोनों पक्षों में निहित अंतरसंबंधों को विकासशील देशों, मुख्यतः भारत के संदर्भ में अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
2. नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को केवल किसी नए अर्थतंत्र अथवा नए आर्थिक आयामों की स्थापना के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। वरन् यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे परिवर्तन का पर्याय है जिसमें विकासशील राष्ट्र अपनी स्वतंत्र पहचान राजनीतिक अस्तित्व एवं निर्णायक सदस्य के रूप में उभर सके।
3. नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना अथवा आर्थिक आयामों के अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पक्षों पर चिंतन करना आवश्यक है।
4. भूमंडलीकरण के युग में उपनिवेशवाद अपने नए रूप नवउपनिवेशवाद के रूप में प्रचलित हुआ है।

#### शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र मूलतः द्वितीयक सूचना स्रोतों पर आधारित है हालांकि प्राथमिक स्रोत भी समाहित किए गए हैं।

किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो या अल्पविकसित हो, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, उसके औद्योगिकीकरण, उन्नत व्यापार, बाजार व्यवस्था, आयातों में कमी, मुद्रा का मूल्य, निर्यात वृद्धि दर, जीवन प्रत्याशा दर, मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर व विदेशी बाजार की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसी प्रकार मुद्रा स्फीति दर मुद्रा के मूल्य, बाजार में मुद्रा की उपलब्धता, मांग तथा पूर्ति में अन्तर, ऋण संकट आदि पर निर्भर करती है। विकसित देशों में औद्योगिकीकरण, उन्नत तकनीकी की उपलब्धता, सुदृढ़ मुद्रा, उच्च मानव सूचकांक, जनसंख्या वृद्धि कम

होने, साक्षरता दर उच्च होने व उत्पादित माल के लिये सहज ही अल्पविकसित देशों के बाजार उपलब्ध होने के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर उच्च प्रतिशतों में है। विकसित देशों में रक्षा उत्पाद, आणविक, तकनीकी उत्पादों के विकासशील देशों को निर्बाध निर्यात के कारण व्यापार संतुलन उनके पक्ष में रहता है। विकसित देशों को केवल कुछ कच्चे माल तथा कुटीर व घरेलू उत्पाद की वस्तुओं का ही आयात करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विकसित देश अपने ऋणों के मकड़जाल में निर्धन देशों को फांसकर उनका दोहन करते हैं जो कि उनकी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को सशक्ता प्रदान करता है। विकासशील व अल्पविकसित देशों में स्थिति उसके विपरीत है। विकासशील देशों में उच्च आधुनिक तकनीकों की अनुपलब्धता, औद्योगिकीकरण की कमी, निम्न साक्षरता दर व मानव सूचकांक, जनसंख्या विस्फोट, कमजोर मुद्रा, तेल, गैस व सशस्त्रीकरण पर बेतहाशा व्यय, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, कमजोर निर्यात, के कारण सकल घरेलू उत्पाद अपेक्षाकृत न्यून रहता है तथा मुद्रा स्फीति की दर उच्च रहती है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नव-स्वाधीन राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने आर्थिक विकास की है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था ने उनके आर्थिक विकास के लिए तीन मार्ग सुझाए हैं –

1. अन्तर्राष्ट्रीय ऋण,
2. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता एवं
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

शुरू में विकासशील राष्ट्रों को ये तीनों मार्ग बहुत आकर्षक प्रतीत हुए तथा वे पश्चिमी राष्ट्रों के जाल में फंस गए। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता ने उन्हें पुनः आर्थिक साम्राज्यवाद के दुष्क्रम में फंसा दिया है तथा सहायता देने वाले राष्ट्र उनकी गृह नीति तथा विदेश नीति में हस्तक्षेप करने लगे हैं। उन्हें दूसरी अनुभूति यह हुई कि अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का चढ़ता भार उनकी अर्थ-व्यवस्था का दम घोटता जा रहा है तथा वे सिर से पांव तक कर्ज में डूबते जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का लाभ तभी संभव था, जब पश्चिमी राष्ट्र के उद्योगों पर विदेशी पूंजीपतियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण और दोहन। अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान और उनके ब्याज का भुगतान तभी संभव था, जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें विकासशील राष्ट्रों के अनुकूल होती तथा विकसित राष्ट्र मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते, परन्तु ऐसा नहीं हुआ तथा तीसरे विश्व के विकासशील राष्ट्रों को एक ओर विश्व की वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं और संगठनों के भीतर तथा बाहर अस्तित्व का संघर्ष जारी रखना पड़ा एवं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा राष्ट्रमंडल, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन आदि के माध्यम से नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की मांग उठाने के लिए विवश होना पड़ा।

#### नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के मूल बिन्दु

1. नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम उद्देश्य है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भेदभाव प्रवृत्ति पर आधारित है जिसमें तृतीय विश्व की समुचित

भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। तृतीय विश्व की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नियो की मांग की गई है।

2. नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के तहत उन वैश्विक आर्थिक व व्यापारिक नियम व मानदण्डों में परिवर्तन हेतु दबाव बढ़ा जिससे कि विश्व स्तर पर एक उत्तरदायी पारदर्शी सहयोगी एवं संवेदनशील अर्थव्यवस्था का बहुआयामी विकास हो।
3. पूंजी एवं तकनीक के व्यापक स्तर पर गरीब राष्ट्रों को हस्तान्तरण किए जाने, तृतीय विश्व के राष्ट्रों को व्यापक स्तर पर पूंजी मुहैया कराने हेतु समुचित ठोस मानदण्ड तैयार किए जाने हेतु दबाव बढ़ाया जाय।
4. विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में संरक्षणवादी नीतियों पर अंकुश हेतु प्रयत्न हों।

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सन्दर्भ में कई मुद्दे उभर कर सामने प्रकट होते हैं।<sup>1</sup> यथा—

1. अमीर राष्ट्रों द्वारा गरीब राष्ट्रों के लिए अपने संसाधनों का हस्तान्तरण करना। इस सन्दर्भ में अनुमानित राशि लगभग विकसित देशों के सकल उत्पादन का 0.7 प्रतिशत होनी चाहिए।<sup>2</sup>
2. पुरानी अर्थव्यवस्था को अराजक व अतार्किक होने के कारण छोड़कर नई न्यायोचित व तार्किक ढांचे की पुनर्रचना।
3. तीसरी दुनियां के देशों द्वारा आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास करना।
4. तीसरी दुनिया के देशों को विकसित देशों की उन्नत तकनीक के प्रयोग की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
5. तीसरी दुनिया के देशों को अमीर देशों के बाजारों में पहुंच का हक होना चाहिए। इन सभी मुद्दों के अन्तर्गत तीसरी दुनिया के देश नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करने के हकदार हैं।

नई अर्थव्यवस्था के तहत दो स्तरों पर—(अ) विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य जिसे कि उत्तर-दक्षिण संवाद कहा गया तथा (ब) विकासशील राष्ट्रों के मध्य परस्पर सहयोग हेतु संवाद जिसे कि दक्षिण-दक्षिण संवाद कहा गया, प्रारंभ हुए। विकासशील देशों के दबावों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1960 के दशक को प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ विकास दशक घोषित किया।<sup>3</sup> 1961 में 'संयुक्त राष्ट्र पूंजी कोष' की स्थापना की गई।<sup>4</sup> 1962 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन (अंकटाड) की स्थापना हुई तथा 1970 के दशक को संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विकास दशक घोषित किया गया।<sup>5</sup>

#### नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व भूमंडलीकरण

नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। अतः भूमंडलीकरण, इसके प्रभावों एवं आने वाले समय में इसके समालोचनात्मक स्वरूप को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन। पूरे विश्व में एक केन्द्रीय व्यवस्था का होना भूमंडलीकरण है।<sup>6</sup> 'भूमंडलीकरण' का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था का 'एकीकरण' शेष विश्व के साथ

करने के रूप में लगाया जाता है। यही एकीकरण आर्थिक नीतियों के स्तर पर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के स्तर पर तथा उत्पादन तकनीक के प्रयोग व हस्तांतरण के स्तर पर होता है। आज संचार क्रांति ने विभिन्न देशों के बीच की दूरी पाट दी है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने को समस्त विश्व से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। डेविड हैल्ड ने भूमण्डलीकरण को सामाजिक संबंधों में एक खिंचाव, प्रवाह की तीव्रता, संस्कृतियों के बीच संबंध बताया है।<sup>8</sup> एन्थनी गिडेन्स ने भूमण्डलीकरण को आधुनिकता का परिणाम बताया।<sup>9</sup> अर्मत्य सेन ने इसे पश्चिमी न मानकर इसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक बताई।<sup>10</sup> भूमण्डलीकरण वैश्विक स्तर पर दूरसंचार के व्यापक ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है।<sup>11</sup>

भूमण्डलीकरण का उच्चस्तरीय स्वरूप 'वैश्विक गाँव' की अवधारणा को साकार करने में निहित है, वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही भूमण्डलीकरण है। अतः भूमण्डलीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने एक बाजार का रूप ग्रहण कर लिया है। भूमण्डलीकरण समकालीन विश्व इतिहास की प्रमुख विशेषता है। आज सम्पूर्ण विश्व सिमट कर एक वैश्विक गाँव में रूपांतरित हो गया है। यह सत्य है कि आज भी अलग-अलग देश और राष्ट्र मौजूद हैं, किन्तु यह घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यह अन्तर्क्रिया और घनिष्ठ सम्बन्ध जीवन के हर क्षेत्र में अर्थात् अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, यातायात, संचार तथा राजनीति में है। यह एक अलग बात है कि भूमण्डलीकरण ने प्राचीन आर्थिक तरीकों से परे हटकर एक नवीन आर्थिक स्थिति पैदा की है। जैसे-व्यापार एवं धन में उदारीकरण की नति से राज्य नियंत्रण को कुछ हद तक हटा दिया है। आज एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आदान-प्रदान कुछ ही क्षण में हो सकते हैं, लेकिन इससे कई नुकसान भी हैं। भूमण्डलीकरण से आर्थिक नव उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त होगा। यह वह मार्ग है, जिस पर चलकर गरीब राष्ट्र अपने पाँव खो बैठेंगे और इस मार्ग का अन्त पराधीनता की अँधेरी कोठरी में जाकर होगा। भूमण्डलीकरण के फलस्वरूप गरीब देशों की राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर कुठाराघात हो सकता है और उनकी राष्ट्रीय सम्प्रभुता समाप्त सी हो सकती है। भूमण्डलीकरण की अवधारणा के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष हैं, किसी भी एक पक्ष को ही महज उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि केवल नकारात्मक परिणामों के भय से विश्व विकास का संकल्प नहीं छोड़ा जा सकता है। भूमण्डलीकरण ने सारे विश्व को सशक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण करने का एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया है, हमें इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए, यह समय किनारे-किनारे चलने का नहीं है, नई चुनौतियों से जूझने का है। राष्ट्रियता की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की भावना को बढ़ाने का है।

भूमण्डलीकरण जो कि नितांत राजनीतिक प्रक्रिया भले ही हो परंतु यह विकास के समस्त पक्षों-सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि को समाहित करता

है। भूमण्डलीकरण से निवेश की सुविधा, पूंजी का प्रवाह बढ़ना, बाजार का बढ़ना, उत्पादन में वृद्धि, तकनीकी का तीव्र विकास आदि लाभ होते हैं।<sup>12</sup> भूमण्डलीकरण के सैद्धांतिक पक्ष में समस्त विश्व को एक नई इकाई स्वरूप प्रदान कर पिछड़े एवं अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर उनको सुदृढ़ बनाना लक्ष्य रखा गया परंतु वास्तविकता यह नहीं है क्योंकि भूमण्डलीकरण के नाम पर विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप की घटनाएं अप्रत्याशित रूप में बढ़ गई हैं। भूमण्डलीकरण को विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के शोषण की एक नई तकनीकी के रूप में भी देखा जा सकता है। यद्यपि उक्त कथन से शत-प्रतिशत सहमत नहीं हो सकते, परंतु इस कथन की शत प्रतिशत असत्यता को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

### निष्कर्ष

इस प्रकार नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे परिवर्तन का पर्याय है जिसमें विकासशील राष्ट्र अपनी स्वतंत्र पहचान, राजनीतिक अस्तित्व एवं निर्णायक सदस्य के रूप में उभर सकें। इस अवधारणा से यही अभिप्राय है कि विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्र जो आर्थिक स्वावलम्बन के लिए दृढ़ संकल्प हैं, साम्राज्यवाद से मुक्त होकर अपना विकास करें तथा इस अर्थव्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य व्यापार व्यवस्था में अपेक्षित सुधार को समाहित करना भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया से जोड़कर देखा गया है। भूमण्डलीकरण से अलग इस अवधारणा को नहीं रखा जा सकता। यद्यपि भूमण्डलीकरण के नकारात्मक व सकारात्मक दोनों पक्षों की चर्चा की जाती है। विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों पर आरोप लगाते हैं कि भूमण्डलीकरण इनकी एक सोची समझी चाल है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया का विरोध कर नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना असंभव है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज, ए 5559, जी. ए. रेजो. 3201 पूरक एस (VI) छठा विशेष अधिवेशन 1974
2. डॉ. जी. वी. नेमा, डॉ. डी. सी. त्रिपाठी, "भारत एवं विश्व" 2012, प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, त्रिपोलिया, जयपुर, वितरक विश्व भारतीय पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 89।
3. डॉ. जी. वी. नेमा, डॉ. डी. सी. त्रिपाठी, "भारत एवं विश्व" 2012, प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, त्रिपोलिया, जयपुर, वितरक विश्व भारतीय पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 89
4. संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज, ए/5100, जी. ए. रेजो. 1706, पूरक 17, 1961
5. संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज, आर्थिक व सामाजिक परिषद्, रेजो. 917, पूरक 34, 1962
6. संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज, टी. डी./बी./329/एडी. 5, 1970

7. डॉ. पुष्पेश पंत, श्री पाल जैन, डॉ. राखी पंचौला, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध: सिद्धान्त और व्यवहार, 2016-17, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृष्ठ. 303
8. तपन विस्वाल, 2013, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, मैकमिलन पब्लिशर्स इण्डिया लि. देहली, पृष्ठ 269
9. तपन विस्वाल, 2013, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, मैकमिलन पब्लिशर्स इण्डिया लि. देहली, पृष्ठ. 269
10. तपन विस्वाल, 2013, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, मैकमिलन पब्लिशर्स इण्डिया लि. देहली, पृष्ठ. 293
11. आर.सी.वरमानी, 2016,समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ 201
12. डॉ. पुष्पेश पंत, श्री पाल जैन, डॉ. राखी पंचौला, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध: सिद्धान्त और व्यवहार, 2016-17, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृष्ठ. 303-304

**वेबसाइट**

1. [www.google.com](http://www.google.com)
2. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)